



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2007/कार्तिक 24, 1929

No. 503]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2007/KARTIKA 24, 1929

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 717(अ).—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2002 का 39) की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 2002 में,—

(i) नियम 11 के उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यदि ऐसा कोई सदस्य, केंद्रीय रजिस्ट्रार के निदेश पर दोनों बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की सदस्यता से हटाया गया है तो ऐसे किसी सदस्य के आवेदन पर ऐसी कोई प्राथमिक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने सदस्य के रूप में ग्रहण करने के लिए विचार कर सकेगी”;

(ii) नियम 19 के उप-नियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) नियम 32 के उप-नियम (8) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु अपील प्राधिकारी, ऐसा आदेश, उन मामलों के सिवाय जहां किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश, रोक या अवरोध या व्यादेश है, 180 दिन की अवधि के भीतर पारित करेगा”;

(iv) नियम 33 के उप-नियम (5) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि अपील प्राधिकारी, ऐसा आदेश, उन मामलों के सिवाय जहां किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश, रोक या अवरोध या व्यादेश है, 180 दिन की अवधि के भीतर पारित करेगा”;

(v) नियम 36 के उप-नियम (1) में, “उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा” शब्दों के पश्चात् “जो

सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार या उसके समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(vi) नियम 37 में,—

(क) उप-नियम (5) के खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) उप-नियम (3) के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा जारी मांग पत्र में, निर्णीत ऋणी का नाम, शोध्य रकम, जिसमें व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित हैं, और उस व्यक्ति को, जिसको मांग पत्र दिया जाएगा, संदाय किया जाने वाला बट्टा, संदाय के लिए अनुज्ञात समय तथा असंदाय की दशा में कुर्क और विक्रय की जाने वाली संपत्तियों का विवरण, दिया जाएगा। मांग पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, विक्रय अधिकारी, निर्णीत ऋणी पर मांगपत्र की तामील करेगा या करवाएगा। यदि निर्णीत ऋणी, अनुज्ञात समय के भीतर मांग पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय में असफल होता है";

(ख) उप-नियम (8) के खंड (i) में, "उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा" शब्दों के पश्चात् "जो किसी राज्य में सहकारी सोसाइटियों के सहायक रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे का न हो या उसके समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-नियम (11) के खंड (ख) के परंतुक में, "जहां विक्रय अधिकारी का" शब्दों के पश्चात् "लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

3. अनुसूची के पैरा 1 में, उपपैरा (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सदस्यता, एक हजार से अधिक है वहां रिटर्निंग आफिसर, जैसा समुचित समझे, ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में मतदान केंद्रों का प्रबंध कर सकेगा। इन मतदान केंद्रों में डाले गए मतपत्रों की, साधारण सभा के अधिवेशन में निर्वाचन और घोषित किए जाने वाले परिणामों के प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण सभा के स्थान पर, गणना की जाएगी।"

[फा. सं. एल-11012/2/2002-एल एंड एम]

सतीश चंदर, संयुक्त सचिव

टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सं. सा.का.नि. 700(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2007

**G.S.R. 717(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 124 of the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 (39 of 2002), the Central Government hereby makes the following amendments to the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Rules, 2007.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Multi-State Co-operative Societies Rules, 2002,—

(i) in rule 11, after sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if on direction of the Central Registrar such a member has been removed from the membership of both the Multi-State Co-operative Societies, on application of such a member any of such primary Multi-State Co-operative Society may consider to admit such a person as its member";

(ii) in rule 19, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted;

(iii) in rule 32, in sub-rule (8), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that the Appellate Authority shall pass such order within a period of 180 days except in the cases

where there is any order, stay or restraint or injunction from any competent court”;

- (iv) in rule 33, in sub-rule (5), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the Appellate Authority shall pass such order within a period of 180 days except in the cases where there is any order, stay or restraint or injunction from any competent court”;

- (v) in rule, 36, in sub-rule (1), after the words “by any person authorized by him” the words “not below the rank of Assistant Registrar of Co-operative Societies in a State or an officer of equivalent rank” shall be inserted;

- (vi) in rule 37,—

- (a) in sub-rule (5), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely :—

“(aa) The demand notice issued by the recovery officer under sub-rule (3) shall contain the name of the judgement debtor, the amount due, including the expenses, if any, and the batta to be paid to the person who shall have the demand notice, the time allowed for payment and in case of non-payment, the particulars of the properties to be attached and sold. After receiving the demand notice, the time allowed for payment and in case of non-payment, the particulars of the properties to be attached and sold. After receiving the demand notice, the sale officer shall serve or cause to be served demand notice upon the judgement debtor. If the judgement debtor fails to pay the amount specified in the demand notice within the time allowed”;

- (b) in sub-rule (8), in clause (i), after the words “any other person authorized by him” the words “not below the rank of Assistant Registrar of Co-operative Societies in a State or an officer of equivalent rank” shall be inserted;

- (c) in sub-rule (11), in clause (b), in the proviso, after the words “the recovery officer is satisfied”, the words “for the reasons to be recorded in writing” shall be inserted;

3. In the Schedule, in para 1, after sub-para (e), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that where the membership of a multi-State co-operative society exceeds one thousand, the returning officer may arrange for polling booths in the area of operation of such a Multi-State Co-operative Society, as deemed appropriate. Ballots cast in these polling booths shall be counted at the place of the General body convened for the purpose of election and results to be declared in the general body meeting.”

[F.No.L-11012/2/2002-L & M]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.

**Note .—**The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 700(E), dated the 2nd December, 2002.